संसदीय चुनाव 2014

संसद
के लिए
किसानों को वोट

आपके संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार वास्तव में किसान हैं और चुनाव में भाग ले रहा है, कृप्या उसे ही वोट दें। यदि वहां दो से अधिक किसान चुनाव लड़ रहे हैं तो उसी को वोट दें जिसके जीतने के अवसर अधिक हों। हमें संसद में अधिक से अधिक किसानों की आवश्यकता है।

संसदीय चुनाव 2014 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और किसानों की एक संस्था होने के नाते हमने देखा है कि संसद या केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसानों की भागीदारी नगण्य है। राजनीतिक दलों को हमारा सीधा संदेश है कि वास्तविक किसानों को लोकसभा का टिकट दें और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी अनुपातिक भागीदारी का वादा करें ताकि अच्छी नीतियां बनाई जा सकें और उन्हें लागू किया जा सके। इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किसानों को शामिल करना अति महत्वपूर्ण है। गैर–सरकारी संस्थाओं पर अत्यधिक विश्वास करने से सभी किसानों को हानि पहुंची है। नीति निर्माताओं में नीतियां लागू करने की कमी के परिणामस्वरूप से लाभकारी सिद्ध नहीं हुई हैं क्योंकि नीति निर्माता अधिक शिक्षित तो होते हैं और उन्हें ज्ञान भी होता है किंतु उन्हें वास्तविक स्थिति (जमीनी हकीकत) मालूम नहीं होती। वर्तमान सरकार किसानों को अपने ही कार्यक्रमों की सूचना देने में असफल रही है। गैर–संगठित किसानों को गंभीरता से नहीं लिया जाता बल्कि नीतियों में उनके परामर्श को भी हल्के में लिया जाता है। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है और इस प्रकार सत्ताधारी दल और किसान दोनों ही प्रभावित हैं।

पिछले कुछ सप्ताह में देश के बहुत से भागों में भारी वर्षा व ओलावृष्टि से 10000 करोड़ रू. से अधिक मूल्य की फसलों की हानि होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को कुछ प्रतिपूर्ति या मुआवजा देना समस्या का समाधान नहीं है बल्कि हमें फसल बीमा नीति लागू करके स्थाई समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। अस्थाई मौसम होने से कृषि क्षेत्र में फसलों को हानि पहुंचना एक सामान्य घटना है। हमारा सरकार को सुझाव है कि किसानों की फसलों के बीमा के लिए वह 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करें। वर्तमान सेलफोन टावर्स की सुविधाओं का उपयोग मौसम के आंकड़े इकट्ठे करने, इनका विश्लेषण करने तथा मौसम की सूचना प्रत्येक सेलफोन पर देने के लिए किया जाना चाहिए।

मौसम का परामर्श, सूचना देने और फसल का बीमा करने से किसानों का जोखिम बहुत कम हो सकता है। यदि इसे लागू कर दिया जाए तो भारत में किसानों की आत्महत्या की दर में जबरदस्त कमी आ सकती है।

अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि आर्थिक सहायता देने से अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसकी असमानता में कमी लाई जा सकती है, बशर्ते कि कृषि क्षेत्र को भी समान अवसर प्रदान किए जाएं। अगली सरकार को अनिवार्य रूप में खेती की भूमि के आकार के अनुपात में ही आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इस प्रकार बिना किसी अतिरिक्त लागत या खर्चे के अधिकतम किसानों को लाभ मिल सकेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहन देना चाहिए। रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से खाद्य प्रसंस्करण में यह भिन्न है। यह केवल तब ही लाभकारी हो सकता है जब बंपर उत्पादन हुआ हो और किसानों को प्रति एकड़ भूमि के लिए अधिक पैसा मिले। ऐसा होने पर खाद्य मूल्यों में स्थिरता और खाद्य मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण हो सकेगा। भारत वर्ष में विभिन्न शहरों में 10000 किसान मंडियों के लिए जगह बनाई जाए। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कृषि उत्पादों की बिक्री पर अधिकतम 2 प्रतिशत का ही कमीशन दिया जाए। कृषि उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। आयात और निर्यात नियंत्रण के लिए मनमाने निर्णय लागू न किए जाएं और एक उचित नीति तैयार की जानी चाहिए।

कीटनाशकों का अधिकतम और गलत उपयोग करने से किसानों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और वातावरण के लिए भी यह नुकसानदायक है। दुकानदार और व्यापारी नकली कीटनाशक बेचकर किसानों को लूट रहे हैं। ये दुकानदार सामान्यतः वही औजार और वस्तुएं किसानों को बेचते हैं जिनमें उन्हें अधिक लाभ मिलता है। ऐसे व्यर्थ के उपकरणों और वस्तुओं की किसानों को आवश्यकता भी नहीं होती। अतः हमारा सुझाव है कि एक कानून लागू करके फार्मेसिस्ट की तरह कृषि उपकरणों और सामग्री को बेचने वाली प्रत्येक दुकान पर अनिवार्य रूप से एक प्रशिक्षित कृषि केमिस्ट/ग्रेजुएट होना चाहिए।

इस और अन्य समस्याओं का सामना भारतीय कृषि क्षेत्र में किसानों को करना पड़ रहा है और इन्हें तभी सुलझाया जा सकता है जब किसानों को नीतियां तैयार करने में शामिल किया जाए ताकि इन्हें बेहतर, कारगर और वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

भारत कृषक समाज का 37वां राष्ट्रीय सम्मेलन 23 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पिछले वर्षों की गतिविधियों की सूची इस अंक में दी गई है।

भारत कृषक समाज की पिछले 12 महीनों की गतिविधियों की सूची

प्रकाशनों की सूची

1. फॉरमर्स फोरमः द्विमासिक अंग्रेजी पत्रिका
2. कृषक समाचारः मासिक अंग्रेजी एवं हिन्दी अखबार

अध्ययनों/रिपोर्ट की सूची

1. सामाजिक विकास परिषद् द्वारा वर्ष 2012 में 'इंस्टिटयूशनल क्रेडिट, फार्म प्रोडक्टिविटी एंड फार्म डिस्ट्रैस'
2. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डैवलपिंग सोसाइटीज़ द्वारा वर्ष 2013 में 'स्टेट ऑफ इंडियन फॉर्मर – ए सर्वे'

आयोजित गोष्ठियां/सम्मेलनों (राज्य स्तरीय घटनाओं के अतिरिक्त) की सूची

राष्ट्रीय स्तरीय किसानों का अधिवेशन

पुष्कर, (राज.) 21 मार्च, 2013
इस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं पर वार्तालाप किया गया जैसे, उनकी उपजों का लाभकारी मूल्य देना, विपणन, उर्वरक और बीजों की आपूर्ति, कृषि ऋण देना आदि।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- श्रीमती मार्गेट आल्वा, माननीय गर्वनर, (राज.)
- श्रीमती नसीम अख्तर, शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार

कृषि में फॉसिल फ्यूल्स पर सम्मेलनः भारतीय किसानों पर प्रभाव
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

इस सम्मेलन में भारतीय कृषि में फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ते उपयोग का प्रभावः खाद्य, उर्वरक और तेल पर आर्थिक सहायता तथा देश के विकास की योजनाओं हेतु निधियों की उपलब्धता पर वार्तालाप किया गया।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- श्री मुकेश कुमार आनंद, सहायक प्रोफैसर, नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी
- श्री ऋतुराज, निदेशक, एशिया टैक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, जॉन डीरे इंडिया प्रा. लि.
- श्री के.एम. टंडन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उर्वरक एवं उर्जा, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स
- श्री सतीश चंद्र, महानिदेशक, द फर्टिलाइजर एसोशिएशन ऑफ इंडिया
- श्री एस.पी. सिंह, सीनियर फैलो एंड कोआर्डिनेटर, इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग
- कु. अनुमिता राय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, रिसर्च एंड एडवोकेसी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट

सीएसडी के सहयोग से संस्थागत ऋण और कृषि संकट के संदर्भ में भारतीय कृषि की उभरती चुनौतियों पर गोष्ठी
नई दिल्ली, 6 से 7 जून, 2013

इस सम्मेलन में पिछले दशक की कृषि नीतियों को देखने का प्रस्ताव था और संस्थागत ऋण पर प्रमुख ध्यान देते हुए भारतीय कृषि में नई उभरती चुनौतियों के बारे में वार्तालाप हुई।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- श्री तारिक अनवर, माननीय कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार
- प्रोफ. मुकंद दुबे, अध्यक्ष, सीएसडी

- डॉ. हक, निदेशक, सीएसडी
- डॉ. प्रकाश बख्शी, अध्यक्ष, नबार्ड
- श्री जे.एन.एल. श्रीवास्तव, इफको प्रतिष्ठान
- प्रोफे. उत्सा पटनायक, जेएनयू
- प्रोफ. रमेशचंद, एनसीएपी
- डॉ. बिश्वजीत धर, आरआईएस
- श्री सुरेंद्र सिंगला, पूर्व वित्त मंत्री, पंजाब
- डॉ. दिलीप सिंह, अपर सचिव, सहकारी संस्थाएं और सहकारी ऋण, भारत सरकार

'भारत में कृषि उत्पादों के मूल्य' पर सम्मेलन
नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2013

इस सम्मेलन में भारत में कृषि वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार में विचार विमर्श और वाद–विवाद हुआ।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- डॉ. अभिजीत सेन, सदस्य, योजना विभाग
- डॉ. अशोक गुलाटी, अध्यक्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- डॉ. रमेश चंद, निदेशक, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति केंद्र
- डॉ. बिबेक देबरॉय, प्रोफैसर, नीति अनुसंधान केंद्र
- श्री आलोक सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एफसीआई
- डॉ. देवेंद्र शर्मा, खाद्य नीति विश्लेषक एवं एक्टिविस्ट
- श्री सुनीत चोपड़ा, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कृषि कर्मचारी संघ एवं सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) केंद्रीय समिति

कृषि विज्ञान के एडवांसमेंट न्यास के सहयोग से 'नवीन कृषि खोज' पर राष्ट्रीय कार्यशाला
नई दिल्ली, 3–5 सितंबर, 2013

इस कार्यशाला का प्रायोजन किसानों के लाभ के लिए की गई महत्वपूर्ण खोजों पर वार्तालाप करना और उनकी पहचान करना था ताकि इनको व्यापक पैमाने पर अपनाकर इन्हें वैध रूप में, परिष्कृत अपनाकर प्रचार किया जाए और पूर्ण बड़े पैमाने पर वांछित लाभ मिल सके।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- डॉ. आर.एस. परोडा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग
- डॉ. एस अयप्पन, सचिव, डेयर एंड डीजी, आईसीएआर
- डॉ. के.डी. कोकेटे, डीडीजी (एकस्ट.) आईसीएआर
- डॉ. एच.एस. गुप्ता, निदेशक, आईएआरआई
- डॉ. पी. एल. गौतम, उपाध्यक्ष, टीएएएस
- डॉ. एस.ए. पाटिल, अध्यक्ष, कर्नाटक कृषि मिशन
- डॉ. बी.एस. ढिल्लन, वाइस–चांसलर, पीएयू, लुधियाना
- डॉ. जे. एस. सामरा, सीईओ, एनआरएए
- डॉ. के.एल. चढ्ढा
- डॉ. के.एम.एल. पाठक, डीडीजी (पशु विज्ञान)
- डॉ. ऐ.के. श्रीवास्तव, निदेशक एनडीआरआई
- डॉ. एस.एस. जोहल
- डॉ. मृत्युंजय
- डॉ. पी.के. जोशी, निदेशक, आईएफपीआरआई, साउथ एशिया

'भारतीय कृषि में अनुसंधान एवं विकासः मुद्दे और चुनौतियां' पर सम्मेलन
नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 2013

भारत में किसानों के संदर्भ में कृषि अनुसंधान एवं विकास संबंधी मुद्दों और चुनौतियों को उठाना जिनमें विस्तार सेवाओं को मजबूत करना शामिल है, विशेषकर वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- डॉ. वाई.के. अलग, चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात
- डॉ. स्वपन कुमार दत्ता, उप–महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
- प्रोफ. आर.बी. सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी
- श्री राजेश कृष्णन, सह–संयोजक, कोइलिशन फॉर ए जीएम फ्री इंडिया
- श्री प्रबीर पुरकायस्थ, अध्यक्ष, नॉलेज कॉमन्स एंड संस्थापक सदस्य, दिल्ली विज्ञान फोरम
- डॉ. पीटर केनमोरे, एफएओ के भारत में प्रतिनिधि
- डॉ. वी.वी. सदामते, एग्रिकल्चरल कन्वर्सेंज एक्सपर्ट

भारतीय प्रबंधन संस्था, कोलकत्ता के सहयोग से 'ग्लोबल वौल्यू चेन के समकक्ष भारतीय कृषि को ले जानाः अवसर और चुनौतियां' पर सम्मेलन
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2014

इस सम्मेलन में उपरोक्त विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्तालाप और वाद–विवाद किया गया।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- श्री सिराज हुसैन, सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- प्रोफ. अर्पिता मुखर्जी, प्रोफैसर, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संपर्कों संबंधी अनुसंधान की भारतीय परिषद्
- प्रोफ. पार्थ प्रतिम पाल, एसोशिएट प्रोफैसर, इकोनोमिक्स ग्रुप, भारतीय प्रबंधन संस्था, कोलकत्ता
- श्री तरूण जैन, उपाध्यक्ष, खाद्य सेवाएं एवं कृषि, टैक्नोपार्क परामर्शदाता
- श्री संतोष के. देशमुख, मुख्य समन्वयक, कॉर्पोरेट रिस्पौंसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जैर इरिगेशन सिस्टम्स लि.
- श्री राजकुमार भाटिया, सचिव, आजादपुर फल एवं सब्जी व्यापारी संघ
- श्री जितेश चंदुभाई पटेल, गुजरात के किसान
- श्री अरनब कुमार हाजरा, निदेशक, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग चैंबर संघ
- प्रोफ. के.एस. चलापति राव, प्रोफैसर, ओद्यौगिक विकास अध्ययन संस्थान

'सुरेंद्र जाखड़ इफको न्यास' के सहयोग से अबोहर, पंजाब में किन्नू मेला
पंजाब, 26 फरवरी, 2014

इस मेले में 1500 किसानों ने भाग लिया। विभिन्न कृषि यंत्रों और उपकरणों के 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया। गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- डॉ. पी.के. अरोडा, निदेशक, क्षेत्रीय फल अनुसंधान स्टेशन, अबोहर
- श्री मिलिंद, मार्गो बायो–कंट्रोल
- श्री बी.डी. जाडे, फर्टिगेशन एक्सपर्ट, जैन इरिगेशन
- श्री संदीप पाटिल, बेयर क्रॉप साइंस
- डॉ. पी.के. मोंगा, रिटा. निदेशक, आर.एफ.आर.एस, पीएयू

स्टडी ऑफ डेवलेपिंग सोसाइटीज के केंद्र द्वारा जारी भारत कृषक समाज कमिशन्ड 'भारतीय किसानों की दशाः एक सर्वेक्षण'
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

देश के 18 राज्यों में 137 जिलों में 5000 किसान परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण कर्ताओं ने जहां भी संभव था उत्तर देने वाले प्रत्येक किसान के एक महिला और एक युवा सदस्य का साक्षात्कार लिया। 11000 से अधिक उत्तर देने वालों ने अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों, आशाओं और वोट की रूचि का विस्तार से उत्तर दिया।

निम्नलिखित वक्ताओं/आलोचकों ने भाग लिया

- श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय
- डॉ. आर.एस. परोडा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग
- डॉ. रमेश चंद, निदेशक, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र
- श्री संजय कुमार, निदेशक, विकासशील समाज के अध्ययन का केंद्र